छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के संस्थापक अध्यक्ष श्री अजीत जोगी जी की प्रेसवार्ता
**विषय:** चिदंबरम जांच एवं पनामा पेपर **दिनांक:** 02 अगस्त, 2017, **स्थान:** दिल्ली

आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार! इस प्रेस कांफ्रेंस में आने के लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ।

2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के लोगों में एक आशा जागी थी कि मोदी जी देश में व्यापक पैमाने में फैले भ्रष्टाचार को न सिर्फ रोकेंगे बल्कि यूपीए सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। तीन साल से ज्यादा हो गए, इनमे से दोनों नहीं हुआ।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध एनडीए सरकार का जो 'जीरो टॉलरेंस' है उसमे जीरो के बाद एक छोटा सा फुल स्टॉप है जो अब पुरे देश को धीरे-धीरे दिखने लगा है। "जीरो" राजनितिक दुश्मनों के लिए और "टॉलरेंस" भाजपा और उसके मित्रों के लिए।

केंद्रीय जांच एजेंसियाँ, लालू प्रसाद यादव जी पर कार्यवाही कर रही हैं, बंगाल में छापे मारे जा रहे हैं, ओडिशा में सरकार को बदनाम करने का खेल चल रहा है, दिल्ली में भी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। आखिर क्यों केवल गैर-भाजपा शासित राज्यों में ही ये तथाकथित भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहीम चल रही है। क्यों भाजपा शासित राज्य एजेंसियों की कार्यवाही से अनछुये हैं।

मैं आज अपनी इस प्रेसवार्ता में आप सभी के माध्यम से देश के सामने दो अत्यंत संवेदनशील और ताज़ा मामलों में कुछ खुलासे करूँगा जिससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध निष्पक्ष होकर कार्यवाही नहीं कर रही है बल्कि राजनितिक दुर्भावना से ग्रसित होकर केवल अपनी राजनितिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध ही कार्यवाही कर रही है।

.....

## १) केंद्र सरकार से मेरा पहला प्रशन ये है किकार्थी चिदंबरम मामले में जांच का दायरा सिमित क्यों हैं ? क्यों बड़ी मछलियों और भाजपा के दोस्तों को बचा रही है सरकार?

- पब्लिक डोमेन में उपलब्ध यह लेटेस्ट **शेयर होल्डर लिस्ट, (संलग्न)** ओडिशा की एक कंपनी (आईएमएफए) इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड की है। यह कंपनी ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद श्री बैजयंत पांडा के परिवार की है जिसके स्वयं श्री बैजयंत पांडा डायरेक्टर भी हैं। बैजयंत पांडा की इसी कंपनी में नलिनी चिदंबरम नामक एक महिला भी शेयरहोल्डर है। और इस महिला का पता **पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम जी के पते (संलग्न) से मिलता है** यानि ये नलिनी चिदंबरम जिनके आईएमएफए कंपनी में शेयर है वो श्री पी चिदंबरम की पत्नी हैं।

- श्री पी चिदंबरम के **२००४, २००९ और २०१४ (संलग्न)** के चुनावी शपथ पत्र यानि एफिडेविट में कहीं भी नलिनी चिदंबरम का आईएमएफए में शेयरहोल्डर होने का उल्लेख नहीं है। जबकि चुनावी शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी चल-अचल संपत्ति का पूर्ण ब्यौरा देने आवश्यक है। जानकारी छुपाना क़ानूनी अपराध है। ये जानकरी किन कारणों से छुपायी गयी, इसका स्पष्टीकरण या तो श्री बैजयंत पांडा जी दें, या चिदंबरम जी दे या फिर सरकार इस देश की जनता को बताये कीआखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। शेयरहोल्डर सूचि में नलिनी चिदंबरम के पिता का नाम चिदंबरम लिखा हुआ है ये भी जांच का विषय है।

- वो पी चिदंबरम जी ही थे जिन्होंने ओडिशा के बीजेडी सांसद श्री बैजयंत पांडा एवं उनके परिवार की कंपनी (आईएमएफए) इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड को आईडीबीआई बैंक द्वारा दिए गए विवादास्पद 2300 करोड़ रुपये की ऋण माफ़ी दिए जाने की एक वकील के रूप में पैरवी की थी। आईएमएफए को मिली 2300 करोड़ रुपये की ऋण माफ़ी को तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी ने जनता के पैसों की खुली लूट बताया था। और बाद में स्वयं 1998 से 2003 के बीच भाजपा शासित एनडीए सरकार ने ही बैजयंत पांडा एवं उनके परिवार की कंपनी (आईएमएफए) को 2300 करोड़ रुपये की ऋण माफ़ी दी थी । मोदी सरकार एक तरफ तो विजय माल्या पर कार्यवाही करने की बात करती है, वो माल्या जो देश के बाहर हैं लेकिन आरबीआई द्वारा जारी बीस कंपनियों की सूचि, जिन्होंने बैंकों से कर्ज लेकर जनता का पैसा डुबाया, और जिनके मालिक देश में ही हैं उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है ? इस सूचि में बैजयंत पांडा एवं उनके परिवार की कंपनी (आईएमएफए) का नाम भी है . लेकिन अब तक जांच क्यों नहीं की गयी ?

- स्वाभाविक है कि देश विदेश में सौ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनियों के मालिक, ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद श्री बैजयंत पांडा की भाजपा से नजदीकियां हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे।

- मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि भ्रष्टाचार को लेकर इस सरकार की कार्यवाही निष्पक्ष नहीं बल्कि भेदभावपूर्ण है और राजनितिक दुर्भावना से प्रेरित है।

- **चिदंबरम-पांडा कड़ी में एक दूसरा पहलु भी है।**

- श्री बैजयंत पांडा की एक कंपनी है ऑरटेल कम्युनिकेशन्स जो कि मीडिया और केबल के बिज़नेस में है। जब सरकार कार्थी चिदंबरम के आईएनएक्स मीडिया को दिलवाए गए ऍफ़आईपीबी डील की जांच कर रही है तो चिदंबरम जी द्वारा उसी दौरान ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद श्री बैजयंत पांडा की कंपनी ओर्टेल कम्युनिकेशन्स को दिए गए एफआईपीबी अप्रूवल की जांच क्यों नहीं की जा रही है ? दोनों कंपनियों को 2007-2008 के दौरान फॉरेन फंडिंग का अप्रूवल दिया गया था। **(ग्राफ संलग्न)**

- ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात तो स्वयं भाजपा के सांसद सुब्रमनियम स्वामी जी कह रहे हैं जिन्होंने इस वर्ष 15 मार्च को आईटी विभाग द्वारा तैयार किये गए 200 पन्नों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि यूपीए सरकार में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी चिदंबरम जी के कार्यकाल के दौरान हुए सभी एफआईपीबी (फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड) अप्रूवलस की सघन जांच की जानी चाहिए।

- दरअसल चिदंबरम मामले को इस सरकार ने जानबूझ कर आईएनएक्स मीडिया के पीटर मुख़र्जी और इन्द्राणी मुख़र्जी तक ही केंद्रित रखा है। सरकार मरे हुए को मारने में लगी है ताकि देश की जनता को दिखा सके की भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है जबकि सच्चाई ये है कि सरकार यूपीए सरकार में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान दिए गए एफआईपीबी (फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड) अप्रूवलस की जांच का दायरा बढ़ाने के प्रति गंभीर नहीं है।

- आखिर क्यों सरकार आईएनएक्स मीडिया के पीटर मुख़र्जी और इन्द्राणी मुख़र्जी के आलावा उन बाकी कंपनियों और उनको मिले एफआईपीबी (फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड) अप्रूवलस की जांच नहीं कर रही है

जिनको चिदंबरम जी और उनके बेटे ने अप्रूवल दिया था। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्थी चिदंबरम के निवास स्थान में छापे मारे गए। छापे के दो दिन बाद कार्थी विदेश भी घूम आये। उसी तरह जिस तरह विजय माल्या घूमने गए और आज तक नहीं आये। कार्थी चिदंबरम के विरुद्ध ऍफ़आईआर दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

- जब स्वयं एनडीए के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी, प्रधानमंत्री को लिखे अपने में पत्र में आईटी की रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं तो सरकार 200 पन्नों की इस आईटी रिपोर्ट सार्वजनिक करे और देश की जनता को बताये कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने कार्तिक चिदंबरम को एफआईपीबी अप्रूवलस के लिए पैसे दिए . क्या इसमें श्री बैजयंत पांडा की कंपनी का नाम भी शामिल है या नहीं, इस बात का खुलासा किया जाना चाहिए .

- मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वो ऍफ़आईपीबी अप्रूवलस में की जा रही जांच का दायरा बढ़ाये और श्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान दी गयी सभी स्वीकृतियों की सघन जांच करे।

.....

## (२) केंद्र सरकार से मेरा दूसरा प्रशन पनामा पेपर खुलासे को लेकर है:

- इस संबंध में मैं आज आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण खुलासे करूँगा वो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी के अगस्ता वेस्टलैंड और पनामा पेपर्स लीक में उनके पुत्र के विदेशी खातों के संबंध में:

- पनामा मामले में मैं, पडोसी देश की नयायपालिका को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि न्याय से बड़ा और जनता से ऊँचा कोई नहीं। पनामा मामले में जिस तरह पडोसी देश के मुखिया को पद से हटाया गया वो केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के उन सभी देशों के लिए एक उदहारण है विशेषकर उन देशों के लिए, जहाँ जनता का पैसा, उच्च पद पर बैठे प्रभावशाली लोग अपने विदेशी खातों में जमा किये हुए है।

- जहाँ तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात है, अगस्ता और पनामा मामले में इसके पूर्व भी प्रशांत भूषण जी और योगेन्द्र यादव जी ने कुछ खुलासे किये हैं , मैं इन खुलासों का दायरा बढ़ाते हुए कुछ और कड़ियों को आपके समक्ष आज रखूँगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और भाजपा सां सद श्री अभिषेक सिंह का नाम अभिशाक सिंह अंकित है लेकिन पता **रमन सिंह जी के निजी निवासस्थान का है** . पनामा पेपर्स से ये साफ़ प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री एवं उनके पुत्र द्वारा भारी भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ में कमाए गए अरबों रुपयों को बोगस कंपनियों के माध्यम से विदेशों खातों में जमा किया गया। छत्तीसगढ़ में हुए नान घोटाले एवं अन्य बड़े घोटालों का पैसा बाहर भेजा गया। हालांकि इन खुलासों की परत अगस्ता वेस्टलैंड सौदे की वजह से खुल रही है लेकिन मामला केवल अगस्ता तक ही सिमित नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा वर्षों से भ्रष्टाचा र से कमाए काले धन को सुनियोजित तरीके से विदेशी खातों में डाला गया। बोगस कंपनियों को खोला और बंद किया गया।

- अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर सौदे में छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने किस नियम के तहत कमीशन एजेंट "शार्प ओशन" को कमीशन दिया ? ऐसे कमीशन एजेंट को करोड़ों रुप ये दिए गए जो भारत में रजिस्टर्ड ही नहीं है। जबकि बिचओलियों पर प्रतिबन्ध तो 1985 में ही लगा दिया गया था। सरकारी रिकार्ड्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने "शार्प ओशन" कंपनी को वर्ष 2008 के शुरुआत में पूरा 15.7 लाख डॉलर बतौर कमीशन दे दिया था

। इसके बाद 3 जुलाई 2008 को अभिषेक की कंपनी क्वेस्ट हाइट्स लिमिटेड खोली गयी .अभिषेक सिंह की क्वेस्ट हाइट्स लिमिटेड खुलने के ठीक 27 दिन बाद "शार्प ओशन" कंपनी को 1 अगस्त 2008 को बंद कर दिया गया। **(दस्तावेज संलग्न )** । इतना ही नहीं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पंजीकृत एवं हांगकांग से संचालित इस कंपनी का व्यापर "प्राइवेट" उल्लेखित है यानि जानबूझ कर जानकारी छुपाई गयी है। तो फिर ऐसी कंपनी को सरकार ने किस आधार पर भारी कमीशन दिया जिसके व्यापर एवं कार्य क्षेत्र के विषय में कोई जानकारी सार्वजनिक है ही नहीं , कौन हैं इस कंपनी के डाय रेक्टर्स ? । क्यों इस कंपनी का बैकग्राउंड नहीं जांचा गया ? केवल अगस्ता वेस्टलैंड के कहने भर से इतनी बड़ी रकम सरकारी कोष से किन नियमों के तहत दी गयी। अगस्ता वेस्टलैंड ऐसी बोगस कंपनियां कमीशन देने के लिए खोलता और बंद करता है।

- प्रश्न केवल अगस्ता वेस्टलैंड की एक डील के पैसों का नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में वर्षों से हो रहे कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के काले धन का है कि आखिर ये जाता कहाँ है। वर्षों से हो रहे नान घोटाले यानि पीडीएस स्केम के 36 हज़ार करोड़ कहाँ गए ? छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के पैसों को विदेशों में कैसे भेजा गया। मुख्यमंत्री एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा व्यापक पैमाने पर सुनियोजित ढंग से पैसों को विदेशी खातों में डाला गया।

- **पहला खुलासा** : (दस्तावेज संलग्न )

- मुख्यमंत्री और उनके सांसद पुत्र अभिषेक सिंह का पैसा स्विस बैंक UBS AG में जमा है। मैँ कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ बल्कि प्रमाणिकता से ये बात कह रहा हूँ। सुराग देना मेरा काम है लेकिन जांच करना जांच एजेंसियों का। मोदी जी अगर काला धन लाने के प्रति गंभीर तो सबसे पहले अभिषेक सिंह के खातों की जांच करके दिखाए। विजय माल्या ने जिस कंपनी "शेयर कोर्प" (SHARE CORP) के माध्यम से देश का पैसा देश से बाहर भेजा उसी कंपनी के माध्यम से रमन सिंह और अभिषेक सिंह का काला धन देश के बाहर गया या यूँ कहिये कि चैनलाइज हुआ। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पंजीकृत कंपनी "क्वेस्ट हाइट्स " लिमिटेड जिसके डायरेक्टर "अभिषेक सिंह " हैं और जिसका पता रमन मेडिकल स्टोर कवर्धा है। अभिषेक सिंह ने बतौर क्वेस्ट हाइट्स का डायरेक्टर होते हुए , "शेयर कोर्प " (SHARE CORP) कंपनी को अपना शेयरहोल्डर नॉमिनी नियुक्त किया । ये वही कंपनी है जिसे भगोड़े विजय माल्या ने भी अपना नॉमिनी नियुक्त किया है . SHARECORP शेयरकोर्प नामक जिस कंपनी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं उनके पुत्र का पैसा स्विस बैंक UBS AG में जमा होता है ये वही कंपनी है जिससे भारतीयों बैंकों को लुटने वाले विजय माल्या का पैसा बाहर जाता था। अभिषेक सिंह ने भी माल्या की तरह "शेयर कोर्प" (SHARE CORP) को इसलिए अपना शेयरहोल्डर नॉमिनी नियुक्त किया ताकि उनकी पहचान छुपी रहे। इसी बोगस कंपनी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं उनके परिवार का अरबों का काला धन स्विस बैंक UBS AG एवं उसके सम्बंधित बैंकों में जमा है। स्विस बैंक UBS AG ने ही "शेयर कोर्प" (SHARE CORP) खोलने में मदद की ताकि इसके माध्यम से जो बैंक खाते का असली मालिक है या जिसके पैसे हैं उसकी असली पहचान को गुप्त रखा जा सके। असल में "शेयर कोर्प" (SHARE CORP) को चलाने वाली कंपनी है पोर्टक्युललिस , ये वही कंपनी है जो जिसके ऑफिस के फ्लोर में अभिषेक सिंह की कंपनी क्वेस्ट हाइट्स का ऑफिस है। मुख्यमंत्री एवं अभिषेक सिंह का विदेश में पैसे का देखरेख, प्लानिंग, बैंक खाते, वगैरह सब कुछ पोर्टक्युललिस ही करती है। पोर्टक्युललिस के डायरेक्टर ग्राहम फरिंहा से पूछताछ करने या संपर्क साधकर मुख्यमंत्री एवं अभिषेक सिंह के विदेशी खा तों एवं पैसों के लेनदेन की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ग्राहम फरिंहा का ईमेल आईडी है Info.BritishVirginIslands@portcullis.co)

- विजय माल्या और मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह दोनों में ही कोई फर्क नहीं है। माल्या ने जनता का पैसा बैंकों के माध्यम से लुट कर विदेश ले गए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र , छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के पैसे को घोटालों के रूप में विदेशों में ले गए। सरकार ने माल्या को तो देश से चुपचाप भगा दिया, और अब रमन सिंह के बचाव में खड़े हो गए हैं जबकि तथ्य और खुलासे सब से सामने हैं। साफ़ प्रतीत होता है कि "न खाऊंगा और न खाने दूंगा वालों के सुर और बोली बदल गयी है।

- **दूसरा खुलासा** : (दस्तावेज संलग्न )

- पनामा पेपर के अनुसार छत्तीसगढ़ के बड़े उद्योगपति कमल किशोर सारदा की भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक आइडियल पोजिशनिंग ऑफशोर (IDEAL POSITIONING OFFSHORE) नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। यह सर्वज्ञात है कि उद्योगपति श्री कमल किशोर सारदा के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी के साथ काफी नजदीकी संबंध हैं . चौंका देने वाला खुलासा ये है कि मुख्यमंत्री के सांसद पुत्र अभिषेक सिंह की कंपनी "क्वेस्ट हाइट्स" और मुख्यमंत्री के करीबी उद्योगपति कमल किशोर सारदा और उनके पुत्र पंकज सारदा की कंपनी आइडियल पोजिशनिंग ऑफशोर (IDEAL POSITIONING OFFSHORE) का ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पता एक ही है। यानि दोनों ही एक ही पते पर रजिस्टर्ड है - Porticullis Trustnet chambers, PO Box, 3444, Roadtown, Tortola, British Virgin Island. मुख्यमंत्री के पुत्र अभिषेक सिंह और छत्तीसगढ़ के उद्योगपति कमल किशोर सारदा की कंपनियों का पंजीयन भी वर्ष 2008 में एक महीने आगे पीछे हुआ है। अभिषेक सिंह की क्वेस्ट हाइट्स 3 जुलाई 2008 को एवं उद्योगपति की कंपनी आइडियल पोजिशनिंग ऑफशोर का पंजीयन 3 जून 2008 को। दस्तावेज संलग्न )

- ये सारी कंपनियां और सारा चक्कर वर्ष 2008 यानि छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष के समय ही हुआ। ये वही समय है जब नान घोटाला चरम पर था। डॉ रमन सिंह चुनाव के पहले ये आश्वस्त नहीं थे कि वो 2008 में उनकी वापसी होगी या नहीं और इसी चक्कर में 2008 में ये सारी बोगस कंपनियां खोली गयी ताकि भ्रष्टाचार के पैसों को विदेशों में भेजा जा सके।

- पिछले साल अगस्ता और पनामा पेपर लीक के खुलासे के बाद मैंने एन्फो र्समेंट डायरेक्टरेट यानि परवर्तन निदेशालय के चीफ श्री कर्नल सिंह को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की । जिसका आज तक एकनॉलेजमेंट तक नहीं आया है . मुख्यमंत्री एवं उनके सांसद पुत्र के विरुद्ध हम सिविल लाइन्स थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए, पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की । हमने लोकसभा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन को पत्र लिखकर अगस्ता वेस्टलैंड जांच पर बनायीं गयी पब्लिक एकाउंट्स कमिटी भाजपा सांसद अभिषेक सिंह को हटाने की मांग की थी क्योंकि उन्हें के पिता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर अगस्ता स्केम में संलिप्त होने के गंभीर आरोप हैं .हमारी इस पत्र का भी आज तक एकनॉलेजमेंट तक नहीं आया है । इसके बाद हमने स्वयं प्रधामंत्री जी को सारी जानकारी देकर मुख्यमंत्री एवं उनके परिवार के सदस्यों तथा दागदार मंत्रियों के विरुद्ध जांच और कार्यवाही की मांग की , उस पत्र का भी आज तक कोई एकनॉलेजमेंट नहीं आया है , कोई कार्यवाही नहीं, कोई जांच नहीं ।

- भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार मैनेजमेंट छोड़कर अब एकनॉलेजमेंट करे।

- मुख्यमंत्री के सांसद पुत्र के विदेशी खाते होना कोई आम बात नहीं है। मुख्यमंत्री के पांच हज़ार दिनों के राज में, छत्तीसगढ़ में की गयी पचास हज़ार करोड़ से ज्यादा की लूट का काला धन इन विदेशी खातों में जमा है। पनामा लीक्स में केवल उन्ही हस्तियों का नाम आया है जिन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया है। जब पनामा में नाम आने के बाद, एक देश की न्यायपालिका उस देश के मुखिया को पद से हटा सकती है तो न खाऊंगा न खाने दूंगा के वादे के साथ आयी सरकार , मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटा सकती . प्रदेश के मुखिया और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा किये गए भारी भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ में आपातकाल की स्थिति बन गयी है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का हर एक मंत्री छत्तीसगढ़ को लूट रहा है। एक के बाद एक रोज नए कारनामे सामने आ रहे हैं।

अगर डॉ रमन सिंह दोषी नहीं है तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करें। अगर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह एवं उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध 2 अक्टूबर 2017 से पहले कार्यवाही नहीं की गयी तो दिल्ली के जंतर मंतर में सैंकड़ों छत्तीसगढ़वासी रिले भूख हड़ताल करेंगे और तब तक करेंगे जब तक छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता को न्याय नहीं मिल जाता।

मैं प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि वो कार्थी चिदंबरम- आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच का दायरा बढ़ाएं और बीजू जनता दल के सांसद श्री बैजयंत पांडा की सौ से ज्यादा कंपनियों के देश विदेश में लेन देन की जांच करें और भाजपा के दोस्तों को भी जांच के घेरे में लेकर निष्पक्ष कार्यवाही करे और पनामा मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को तत्काल पद से हटाकर, उनके एवं उनके पुत्र की संपत्ति की गहन जांच बैठाकर, देश की जनता के सामने एक उदहारण पेश करे .

धन्यवाद

-0-